MPSE 008 (part-1)
STATE POLITICS IN INDIA
Important questions and repeated topics
For both Hindi and English medium students

Topic -1
Role of Governor in Union-State Relations

Acting as a Link between the State and Union Government
The Governor acts as a bridge between the central and state governments, facilitating communication and ensuring that the policies and directions from the Union government are implemented at the state level.
राज्यपाल राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सेतु का काम करते हैं, संचार की सुविधा प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियां और निर्देश राज्य स्तर पर लागू हों।

Ensuring Constitutional Compliance
The Governor ensures that the state government operates within the bounds of the Constitution. They can recommend the President's rule in case of a constitutional breakdown in the state.
राज्यपाल यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करे। वे राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।

Appointment Powers
The Governor has the power to appoint the Chief Minister and other ministers. They also appoint the Advocate General and the members of the State Public Service Commission.
राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। वे महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं।

Financial Responsibilities

Scholarly Minds

The Governor plays a role in the state's financial administration by ensuring that the annual budget is laid before the state legislature and recommending financial bills.
राज्यपाल राज्य की वित्तीय प्रशासन में भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि वार्षिक बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और वित्तीय विधेयकों की सिफारिश करें।

Legislative Functions
The Governor summons and prorogues the sessions of the state legislature and can dissolve the legislative assembly. They also give assent to bills passed by the state legislature.
राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रों को बुलाते और स्थगित करते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। वे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति भी देते हैं।

Emergency Powers
In times of emergency, the Governor has the authority to make decisions and take actions necessary to handle the situation effectively. They act on the instructions of the President of India.
आपातकाल के समय, राज्यपाल के पास स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए आवश्यक निर्णय लेने और कार्यवाही करने का अधिकार होता है। वे भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों पर कार्य करते हैं।
These roles ensure a balance between the autonomy of states and the authority of the Union government, maintaining the federal structure of the country.

इन भूमिकाओं से राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र सरकार के अधिकार के बीच संतुलन सुनिश्चित होता है, जिससे देश की संघीय संरचना बनाए रखी जाती है।

Topic 2
Write a note on linguistic conflict in Assam
Linguistic Conflict in Assam

Scholarly Minds

Assam, a state in northeastern India, has a rich tapestry of ethnic and linguistic diversity, leading to periodic linguistic conflicts. Here is an overview of the main aspects of this conflict:

Historical Background

Assam has historically been a melting pot of various ethnic groups and languages, including Assamese, Bengali, Bodo, and various tribal languages. The arrival of Bengali-speaking migrants during colonial times and later periods intensified the linguistic diversity.
असम ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जातीय समूहों और भाषाओं का संगम रहा है, जिसमें असमिया, बांग्ला, बोडो और विभिन्न आदिवासी भाषाएं शामिल हैं। औपनिवेशिक समय और बाद के समय में बांग्ला-भाषी प्रवासियों के आगमन ने भाषाई विविधता को और बढ़ाया।
Assamese vs. Bengali Tensions

The major conflict often arises between Assamese speakers and Bengali speakers, especially in Barak Valley, where Bengali speakers form a significant portion of the population. The 1961 Language Movement in Barak Valley, where Bengali speakers demanded the recognition of Bengali as an official language, is a notable example.
मुख्य संघर्ष अक्सर असमिया और बंगाली वक्ताओं के बीच होता है, विशेष रूप से बराक घाटी में, जहाँ बंगाली वक्ता जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। 1961 का भाषा आंदोलन, जिसमें बंगाली वक्ताओं ने बंगाली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग की, एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

Official Language Policy
The Assam Official Language Act, 1960, which recognized Assamese as the official language of the state, sparked significant protests from non-Assamese speaking communities, particularly Bengalis. This act was seen as an attempt to marginalize other linguistic groups.

Scholarly Minds

असम राजकीय भाषा अधिनियम, 1960, जिसने असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी, गैर-असमिया भाषी समुदायों, विशेष रूप से बंगालियों से भारी विरोध का कारण बना। इस अधिनियम को अन्य भाषाई समूहों को हाशिए पर धकेलने के प्रयास के रूप में देखा गया।

Ethnic and Linguistic Assertion
Various ethnic groups in Assam, such as the Bodos, have demanded autonomy and recognition of their languages. The Bodo language movement, which resulted in the creation of the Bodoland Territorial Region, is a significant aspect of the broader linguistic conflict.
असम में विभिन्न जातीय समूहों, जैसे बोडो, ने अपनी भाषाओं की स्वायत्तता और मान्यता की मांग की है। बोडो भाषा आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, व्यापक भाषाई संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

The linguistic conflict in Assam is a complex and ongoing issue, reflecting the broader challenges of managing diversity in a multi-ethnic and multilingual society.

असम में भाषाई संघर्ष एक जटिल और चल रहा मुद्दा है, जो बहु-जातीय और बहुभाषी समाज में विविधता के प्रबंधन की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है।

Topic -3
Constitutional Amendments Related to Union-State Relations

7th Amendment (1956)
The 7th Amendment reorganized states on a linguistic basis, significantly altering the political and administrative landscape. This led to a clearer demarcation of state boundaries and administrative jurisdictions, affecting the balance of power between the Union and the states.
7वां संशोधन (1956) ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इससे राज्य

Scholarly Minds

की सीमाओं और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन हुआ, जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है।

42nd Amendment (1976)
Known as the "mini-constitution," this amendment brought about major changes, including the addition of the words "Socialist" and "Secular" to the Preamble. It also transferred five subjects from the State List to the Concurrent List, thereby increasing the legislative powers of the Union government.
"मिनी-संविधान" के रूप में जाना जाने वाला यह संशोधन प्रमुख बदलाव लाया, जिसमें प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों का समावेश शामिल था। इसने राज्य सूची से पांच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, जिससे संघ सरकार की विधायी शक्तियों में वृद्धि हुई।

44th Amendment (1978)
The 44th Amendment sought to restore the balance of power altered by the 42nd Amendment. It removed the primacy given to the Directive Principles of State Policy over Fundamental Rights and ensured that certain aspects of state autonomy were reinstated.
44वां संशोधन 42वें संशोधन द्वारा बदले गए शक्ति संतुलन को बहाल करने का प्रयास किया। इसने राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर दी गई प्राथमिकता को हटा दिया और राज्य की स्वायत्तता के कुछ पहलुओं को पुनः स्थापित किया।

73rd and 74th Amendments (1992)
These amendments aimed at strengthening local governance by establishing Panchayati Raj institutions and urban local bodies, respectively. They decentralized power to local levels, thereby impacting the Union-state dynamic by empowering local governments.
ये संशोधन क्रमशः पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना करके स्थानीय शासन को मजबूत करने का उद्देश्य रखते थे। उन्होंने स्थानीय स्तरों पर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, जिससे स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाकर संघ-राज्य गतिशीलता प्रभावित हुई।

Scholarly Minds

101st Amendment (2016)
The 101st Amendment introduced the Goods and Services Tax (GST), creating a single national market. It significantly impacted fiscal federalism by subsuming various state taxes into a unified tax system, necessitating cooperation between the Union and states through the GST Council.
101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर (GST) को पेश किया, जिससे एकल राष्ट्रीय बाजार बना। इसने विभिन्न राज्य करों को एकीकृत कर प्रणाली में शामिल करके वित्तीय संघवाद पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे GST परिषद के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक हो गया।

These amendments reflect the evolving nature of Union-state relations in India, highlighting the need for a dynamic balance between central authority and state autonomy.
ये संशोधन भारत में संघ-राज्य संबंधों की बदलती प्रकृति को दर्शाते हैं, जो केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य की स्वायत्तता के बीच एक गतिशील संतुलन की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

ScholarlyMinds